

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty

Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad

International Advisory Board

Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken	Hasan Bakfir English Language and Literature Department, Kayseri
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania	George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, IasiMore

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur	Iresh Swami S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University,Solapur	N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	R. R. Yalikal Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	S.KANNAN Annamalai University,TN
	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University
	Sonal Singh, Vikram University, Ujjain	



अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की सामाजिक एवं नेतृत्व विकास पर पंचायत राज का प्रभाव (मध्यप्रदेश के मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में)

Shilawntee Maskare

Research Scholar , Dr B. R. Ambedkar University of Social Sciences,
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Indore (M.P.)

प्रस्तावना—

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक पद्धति का मूल आधार विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी है। पंचायती राज संस्थाएँ उस भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी जड़ें लोगों में मौजूद है। भारतीय समाज में सदियों से जातीय पंचायत प्रचलन में थी, जो स्थानीय स्तर पर अपने समाज की समस्याओं का निपटारा करती थी। परंतु परम्परागत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की



भागीदारी नगण्य थी तथा लम्बे समय तक राजनैतिक सशक्तिकरण से वंचित रही। भारतीय संविधान में स्त्रियों को समान अवसर का अधिकार प्रदान कर जीवन के हर क्षेत्र में भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया है। इस व्यवस्था से स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्तर के महिलाओं की पंचायत राज संस्थाओं में भागीदारी करने के लिए आरक्षण प्रदान किया है। आरक्षण के प्रावधान से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं को प्रथम बार

राजनीतिक में अवसर प्राप्त हुआ। म.प्र. में पंचायतों का गठन मई-जून १९६४ में सम्पन्न हुआ था। ७३वें संशोधन अधिनियम लागू होने के पूर्ण पंचायतों का संचालन प्रायः राज्यों के राजनेताओं की इच्छा या राज्य की नौकरशाही की कार्य कुशलता पर निर्भर करता था। जमीनी राजनीति से महिलाओं को जोड़ने का प्रयास पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आरम्भ हुआ है। जिससे महिलाओं को शक्ति प्रदान कर सरकार द्वारा ३३ प्रतिशत आरक्षण ग्राम पंचायतों में दिया गया था। जो बढ़कर ५० प्रतिशत हो गया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसे यदि यह कहे कि महिला जगत के लिए राजनीतिक संस्कृति का यह प्रथम पड़ाव है जहाँ से उन्हें भविष्य की राजनीतिक संस्कृति की रोशनी मिली है। देश की राजनीतिक गतिविधियों से परिचित हुई और लाल फीताशाहीयों की कुटिल चालों से भी भिन्न हो सकी है। यह पंचायती राज के अधिनियम (१९६३) का ही प्रभाव है कि भारत में १२ लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम एक क्रांतिकारी कदम तथा महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। पूर्व पंचायत राज मंत्री मणिशंकर अय्यर ने इसे बार-बार दोहराया है कि भारत में एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है, जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाई नहीं दे रही है पर उसकी धीमी चाल भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। इतना ही नहीं यह क्रांति एकता-विमर्श के ढांचे में भी बदलाव ला रही है। पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृति में भी परिवर्तन किया है। पंचायती राज में प्रतिनिधित्व की गारंटी मिलने के साथ ही महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में सजग और दक्ष बनाती है। जिससे महिलाएँ देश की योजनाओं के बारे में जानने लगी हैं। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थितियों में सुधार हो रहा है तथा महिला अध्यक्षों, सदस्यों पंचों और सरपंचों में आत्मविश्वास,

राजनीतिक चेतना एवं इच्छाशक्ति के विकास के साथ ही अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से न सिर्फ महिलाओं का विकास हुआ है, अपितु समाज का सही दिशा में विकास होगा। यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के निर्वाह हेतु जरूरी है। इसी सन्दर्भ में, यू. एन. डी. ई. पी. में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाएँ कृपा दृष्टि और दान की मांग नहीं कर रही हैं। महिलाओं का राष्ट्र-निर्माण में योगदान पुरुषों से ज्यादा है। अतः महिलाओं के लिए आरक्षण कोई दान नहीं है बल्कि सामाजिक विकास में उनके योगदान की सिर्फ एक सच्ची मान्यता है। लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंचायती राज ने ग्रामीण विकास को एक नया आयाम दिया। ग्रामीण जनता की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ग्राम नेतृत्व विकसित हुआ। और भागीदारी बढ़ी है एवं ग्रामीण समाज में एक नई पहचान मिली है।

प्रस्तुत शोध आलेख पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी का उनकी सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव (मध्यप्रदेश के मण्डला जिले के विशेष सदरभ में) प्राथमिक आकड़ों पर आधारित है। जिसमें देव निदर्शन विधि के आधार पर ३०० पंचायती राज संस्थाओं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिलाओं को चुनकर प्राथमिक आकड़ों को एकत्रित किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण

शोध के अध्ययन “पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिलाओं की भागीदारी का उनकी सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव (मध्यप्रदेश के मण्डला जिले के विशेष सदरभ में) अध्ययनानुसार प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है।

पंचायत राज अधिनियम १९६३ के लागू होने के दो दशक पश्चात् भी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान की जानकारी बहुत ही कम है। अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया कि गांव का वातावरण आज भी महिलाओं के नेतृत्व के प्रति प्रोत्साहनपूर्वक कम है। कहीं न कहीं परंपरावादी एवं रूढ़िवादी व्यवस्था आज भी महिला नेतृत्व के विकास में बाधक कारक के रूप में हैं।

तालिका क्रमांक 1
पंचायत महिला प्रतिनिधि उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	शैक्षणिक योग्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर	46	15.3
2.	प्राथमिक	182	60.7
3.	माध्यमिक	47	15.7
4.	हाई स्कूल	17	05.7
5.	हायर सेकेण्डरी	04	01.3
6.	स्नातक	03	01.0
7.	स्नातकोत्तर	01	00.3
कुल उत्तरदाता		300	100

उपरोक्त तालिका १ से स्पष्ट होता है कि ६०.७ प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले पाये गये। वही स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त ०.३ प्रतिशत पाए गये। माध्यमिक एवं हाईस्कूल की १५.७ एवं ०५.७ प्रतिशत उत्तरदाता पाए गये। उसी प्रकार हायर सेकेण्डरी एवं स्नातक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता १.३ प्रतिशत और १.० प्रतिशत उत्तरदाता पाए गये।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सर्वाधिक ६०.७ प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं। शिक्षा का निम्न स्तर पाये जाने का कारण मण्डला जिला जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्र होने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तथा प्रकृति प्रेमी होने के कारण समाज के मुख्य धारा से दूर हैं।

तालिका क्रमांक 2
पंचायत महिला प्रतिनिधी उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	वार्षिक आय (हजार रु. में)	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	5000 से कम	12	04.0
2.	6000 से 10000 तक	39	13.0
3.	11000 से 15000 तक	60	20.0
4.	16000 से 20000 तक	65	21.0
5.	21000 से अधिक	126	42.0
कुल उत्तरदाता		300	100

व्यक्ति के जीवन में आय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आय से व्यक्ति की समाज में प्रस्थिति का निर्धारण होता है साथ ही आय के आधार पर व्यक्ति को वर्गों में विभाजित किया जाता है जैसे-उच्च आय वर्ग का व्यक्ति, निम्न आय वर्ग का व्यक्ति एवं मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति। उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 उत्तरदाताओं के परिवारों में वार्षिक आय का विश्लेषण करने पर पाया गया कि ४२.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय २१००० से अधिक है जिनके परिवार में अधिक भूमि, नौकरी एवं व्यापार में संलग्न हैं वहीं ४.० प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय ५००० से कम है जो अति गरीबी रेखा के अर्न्तगत जीवन यापन कर रहे हैं। जो केवल दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं। उसी प्रकार २१.० प्रतिशत परिवारों में १६००० से २०००० आय वर्ग पाया गया तथा २०.० प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार में ११००० से १५००० तक के आय वर्ग पाये गये। तत्पश्चात १३.० प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार में ६००० से ११००० तक वार्षिक आय का ब्यौरा ज्ञात हुआ है।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि अध्ययन क्षेत्र जनजाति बाहुल्य होने के साथ ही आय वर्ग की स्थिति लगभग असमान है। इसलिए अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक ४२.० उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय २१००० से अधिक पाये गये हैं।

तालिका क्रमांक 3
महिला पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	चुनाव का तरीका	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मतदान द्वारा	208	69.3
2.	निर्विरोध	92	30.7
कुल उत्तरदाता		300	100

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम १९६३ को मध्यप्रदेश में २५ जनवरी १९६४ से लागू किया गया। संविधान के अपेक्षानुसार राज्य निर्वाचित आयोग का गठन किया गया एवं त्रिस्तरीय पंचायत को स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु मतदान कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त तालिका क्रमांक ३ में दर्शाया गया है कि ६९.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदान द्वारा चुना गया है वहीं ३०.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। निर्विरोध चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पूरे गाँव में सर्वसम्मति से निर्णय मान्य होते हैं। किन्तु अवलोकन के द्वारा ज्ञात हुआ कि उस ग्राम में उच्च, धनवान एवं शिक्षित वर्ग का आधिपत्य पंचायत में अधिक है, वे लोग जैसा कहते हैं वैसा सर्वमान्य होता है। अर्थात उन्ही लोगों का आधिपत्य है।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि पंचायत राज संस्थाओं में सर्वाधिक ६९.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदान से जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है एवं अब अपने पद का उपयोग कर पंचायत के मिले अधिकारों, एवं कर्तव्यों के बारे में अधिक से अधिक जानने चाहते हैं।

तालिका क्रमांक 4
महिला पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण मिलने सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	295	98.3
2.	नहीं	05	01.7
कुल उत्तरदाता		300	100

नये पंचायत राज अधिनियम के तहत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक

बनाने हेतु शासन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई हैं, चाहे वह पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत व सदस्य या ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच हो। (MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT) उपरोक्त तालिका के समंक यह दर्शाते कि ६८.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि निर्वाचन होने के बाद प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं १.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि हमें प्रशिक्षण के बारे में मालुम नहीं है। यह प्रशिक्षण नहीं मिला है। तत्पश्चात प्रशिक्षण दिया गया है।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सर्वाधिक पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि निर्वाचन के पश्चात पंचायत के कार्य एवं दायित्वों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

तालिका क्रमांक 5

महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत राज संस्थाओं में दिये गये महिला आरक्षण सम्बन्धी जानकारी का विवरण

क्रमांक	महिला आरक्षण सम्बन्धी जानकारी का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	278	92.7
2.	नहीं	22	07.3
कुल उत्तरदाता		300	100

पंचायती राज संस्थाओं में सभी महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है। (जोशी ७ अक्टूबर २०१४ infochange)। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ६२.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को मालुम है कि पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है इनमें वे प्रतिनिधि है जो अपने अधिकार के प्रति जागरूक एवं पंचायत के दायित्वों को जानती है। कार्यों का निर्वहन करती है। चाहे वह अपने परिवार एवं गाँव वालों के सलाह एवं सहमति से करती हो। किन्तु आरक्षण का फायदा लेकर पंचायत प्रतिनिधि बनी हुई है। वहीं ७.०३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों को आरक्षण के बारे में मालुम नहीं है। वे ऐसे पंचायत प्रतिनिधि महिलाये है जिनको पंचायत के महत्ता के बारे में पता नहीं है या फिर अपने मेहनत मजदूरी में लगी हुई रहती है। तथा नाममात्र के पंचायत प्रतिनिधि है।

अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सर्वाधिक पंचायत प्रतिनिधियों को आरक्षण के बारे में मालुम है किन्तु उनको विस्तृत आरक्षण की जानकारी नहीं है।

तालिका क्रमांक 6

महिला पंचायत प्रतिनिधियों का पंचायत राज संस्थाओं में महिला भागीदारी का सामाजिक प्रस्थिति पर प्रभाव पड़ने सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	271	90.3
2.	नहीं	29	09.7
कुल उत्तरदाता		300	100

उपरोक्त तालिका के समंक यह दर्शाते हैं कि ६०.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत राज संस्थाओं में भागीदारी से उनके सामाजिक प्रस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे उनके गाँव में निर्वाचन के पहले नाम से जानते थे, किन्तु अब पद से सम्मानित तथा सम्बोधित करते हैं। अच्छा आव-भगत पंचायत में आने के बाद मिलने लगी है। लोगों के बातचीत करने के तरीके, व्यवहार करने के तरीके में बदलाव आया है। इस प्रकार पंचायत में भागीदारी करने के सामाजिक व्यवहार में बदलाव आया है तथा समाज में अच्छा सम्मान मिलने लगा है। वहीं ६.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में भागीदारी का सामाजिक प्रस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे पहले लोग सम्मान करते थे। वैसे अभी भी करते हैं।

तालिका क्रमांक 7

महिला पंचायत प्रतिनिधियों के राजनीतिक भागीदारी के महत्व सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अपने अधिकारों की जानकारी के लिए	117	47.36
2.	अपने उत्तरदायित्व की जानकारी के लिए	08	03.23
3.	अपने हित-अहित के लिए	60	24.29
4.	प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए	62	25.10
कुल उत्तरदाता		247	100

उपरोक्त तालिका के समंक दर्शाते हैं कि ४७.३६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि अपने अधिकार को जानने के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है, वहीं २४.२६ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि अपने हित तथा अहित को जानने के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है, तथा २५.१० प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है तथा शेष ३.२३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि राजनीतिक भागीदारी महिलाओं के लिए अपने उत्तरदायित्व की जानकारी के लिए आवश्यक है।

अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ४७.३६ प्रतिशत निर्वाचित जनप्रतिनिधि यह मानते हैं कि महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है और वे अपने अधिकारों को जानने के इच्छुक हैं साथ ही प्रभावी नेतृत्व, अपने हित अहित एवं अपने उत्तरदायित्वों को जानने के लिए राजनीतिक भागीदारी आवश्यक मानते हैं। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि महिला प्रतिनिधि राजनीतिक भागीदारी के महत्व को समझने लगी हैं।

तालिका क्रमांक 8
महिलाओं को राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से उनमें नेतृत्व विकास हुआ है

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	263	87.7
2.	नहीं	37	12.3
कुल उत्तरदाता		300	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ८७.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से उनमें नेतृत्व विकास हुआ है। वहीं १२.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से कोई नेतृत्व विकास नहीं हुआ है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि महिलाओं को राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने से उनमें नेतृत्व विकास हुआ है

तालिका क्रमांक 9
पंचायतों में पदाधिकारी के रूप में सशक्त होकर नेतृत्व करती है

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	242	80.7
2.	नहीं	58	19.3
कुल उत्तरदाता		300	100

उपरोक्त तालिका के समंक यह दर्शाते हैं कि ८०.७ प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की पंचायत पदाधिकारी उत्तरदाता सशक्त होकर नेतृत्व करती हैं। जबकि १९.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि पदाधिकारी के रूप में होने के बावजूद वह सशक्त रूप से नेतृत्व नहीं कर पा रही हैं। अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सर्वाधिक पंचायत प्रतिनिधि जिससे सशक्त होकर नेतृत्व करती हैं। हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में सामाजिक गतिशीलता हुई है।

तालिका क्रमांक 10
आपके साथ पंचायत के बैठकों में जातिगत भेदभाव किया जाता है

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	4	01.3
2.	नहीं	296	98.7
कुल उत्तरदाता		300	100

उपरोक्त तालिका के समंक यह दर्शाते हैं कि १.३ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके साथ पंचायत के बैठकों में जातिगत भेदभाव किया जाता है क्योंकि आज भी आंतरिक रूप से छुआछुत किया जाता है बल्कि दिखते नहीं हैं। सामाजिक और मानसिक रूप से उनमें बदलाव नहीं आया है। कहीं न कहीं उनमें ये भावना घर कर गई है। किन्तु पहले जैसा रूप नहीं रहा है। शिक्षित हो चुके हैं। वे पैतृक व्यवसाय से दूर होकर अच्छे स्वच्छ कार्य में लगे हैं। वहीं ९८.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत के बैठकों में किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है। अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि ९८.७ प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत के बैठकों में किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष:-

भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को महसूस किया गया है, कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना है। संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम है। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रभाव महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनितिक प्रस्थिति पर पड़ा है जिसकी वजह से उन्में सामाजिक गतिशीलता आयी है, और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग है। पंचायत की बैठकों में निर्णय की प्रक्रिया के संबंध में आधे से अधिक प्रतिनिधियों के अनुसार बैठकों में निर्णय सर्व सम्मति से होते है, जबकि एक तिहाई प्रतिधियों की पंचायतों में निर्णयों का आधार बहुमत है। साथ ही यह भी बताया गया है कि निरक्षरता पिछड़ापन एवं जागरूकता के अभाव के रहते पंचायत राज के विभिन्न पक्षों की मुख्य जानकारी एवं प्रमुख प्रावधानों से अनभिज्ञता के कारण वह स्वतंत्र कार्य निर्वहन में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अधिकांश महिलाओं ने स्वीकार किया कि सरकार ने महिला सीट आरक्षित कर दी है। आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू होने से स्थानीय सत्ता संरचना में स्थान प्राप्त हुआ है परन्तु यह भी सत्य है कि जिस अनुपात में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उस अनुपात में महिलाओं की भागीदारी तो हुई है, किन्तु उतनी मात्रा में सशक्तिकरण नहीं हो पाया है क्योंकि परिवार एवं समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति आज भी संकीर्ण है। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करने में पुरुष प्रधान मानसिकता रखने वाले एवं तथाकथित उच्च जातियों के दबंग व्यक्ति सहज भाव से उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है, समानता, स्वतंत्रता के साथ-साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है। वास्तविकता यह है कि सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है। शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला जिला, जनपद अध्यक्षा, सदस्यों एवं सरपंचों और पंचों का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा में ही गांव का विकास निहित है “बोलने ,सुनने और निर्णय लेने का हमारा भी उतना ही अधिकार है, जितना कि एक पुरुष प्रतिनिधियों का है।

सुझाव:-

१. युवा पंचायत महिला प्रतिनिधियों को पंचायत राज संस्थाओं में कार्य करने के रुझान को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे पंचायत राज संस्थाओं के विकास के कार्य हेतु तत्पर होकर कार्य कर सकें।
२. अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक पंचायत प्रतिनिधि साक्षर तो है किन्तु हस्ताक्षर तक सीमित हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास पर बल देना चाहिए जिससे शिक्षित जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में नेतृत्व प्रदान कर सकें।
३. अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान होने के कारण पंचायत प्रतिनिधियों की वार्षिक आय कम है इस हेतु उन्हें आय बढ़ाने हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि उनके आय में वृद्धि हो सके।
४. अध्ययन क्षेत्र में शोध के दौरान पाया गया कि ३०.७ प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ है इसका मतलब या तो उनमें नेतृत्व करने की जिज्ञासा नहीं है या फिर वर्तमान में उच्च वर्ग की दबंगता के कारण उनके निर्णय सर्वमान्य होते हैं इस हेतु निर्विरोध चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए ताकि पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए लोगों में चुनाव लड़ने हेतु लालसा एवं जिज्ञासा उत्पन्न हो सके।
५. शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि पंचायत राज संस्थाओं में भागीदारी प्रदान करने पर राजनीतिक सत्ता एवं निर्णय क्षमता का विकास हुआ है। इस हेतु अधिकाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की निर्वाचित महिलाओं को पंचायत में भागीदारी प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

१. सिंह, वी. एन. एवं जनमेजय सिंह २०१० “आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली पृ. १३
२. योजना अक्टूबर २००८ पृ. १७
३. यू. एन. डी. ई. पी. में जारी रिपोर्ट (महिला आरक्षण विधेयक २००६) सेन्टर फॉर सोशल रिसर्च।

**Shilawntee Maskare**

**Research Scholar , Dr B. R. Ambedkar University of Social Sciences,
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Indore (M.P.)**

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org